कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पास, बडी चौपड, जयपुर, राजस्थान–302002)

क्रमांकः एफ4( )/अति.आ./न.नि.ज.है/कम्प्यू/2024/561 दिनांक 15/02/2024

ई–निविदा सूचना संख्या 5/2023–24 की मुख्य शर्ते

1. निविदा दाता (निविदा हेतु अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता) को निविदा शुल्क, अमानता राशि तथा आर.आई.एस.एल. प्रोसेसिंग शुल्क नगर निगम जयपुर हैरिटेज की वेबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर ऑन–लाईन Submission Date and Time से पूर्व जमा करवाकर उससे प्राप्त होने वाली रसीद को स्कैन www.eproc.rajasthan.gov.in कर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
2. निर्धारित दिनांक एवं समय पर निविदा शुल्क, प्रतिभूति राशि तथा प्रोसेसिंग शुल्क जमा नहीं होने पर निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. निविदादाता द्वारा एनेक्सचर A,B,C,D,E,F को स्वयं हस्ताक्षर कर स्कैन करके www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करने पर ही निविदा को मान्य किया जायेगा।
4. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल पाए गए निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी। अतः निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे तकनीकी निविदा, निविदा की शर्तो के अनुसार ही भरें।
5. ऑन–लाईन बिडिंग प्रोसेस हेतु निविदा दाता द्वारा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC) (टाइप III) जैसा की आइ.टी. एक्ट 2008 से प्रावधित है जो ECA द्वारा प्राधिकृत एजेन्सी ie, TCS, Safecrypt, Node आदि संस्थाओं द्वारा उपलब्ध करवाया जा सकता है प्राप्त किया जावे।
6. किसी भी कारण से निर्धारित समय पर ऑन–लाईन बिड प्रस्तुत नहीं होने पर विभाग जिम्मेदार नहीं है अतः निर्धारित समय से पूर्व ही निविदा ऑन–लाईन कार्य सम्पादित कर लिया जावें।
7. निविदा दाता को RTPP अधिनियम 2012 एवं RTPP नियम 2013 की शर्तो का पालन करना होगा।
8. उक्त निविदा वित्त विभाग द्वारा जारी अधिसूचना एफ.2/एफ.डी.(1) एस.पी.एफ.सी. /2017 दिनांक 25.04.2018 तथा आदेश क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1) एस.पी.एफ.सी. /2017 दिनांक 14.05.2018 एवं परिपत्र संख्या 1/2018 दिनांक 30.04.2018 एवं परिपत्र क्रमांक एफ.2/एफ.डी.(1) एस.पी.एफ.सी./2017 दिनांक 11.07.2018 में दी गई सभी शर्तों का पालन करना होगा।
9. निविदादाता द्वारा निविदा में प्रस्तावित दर श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी (Skilled Labour) दर रूपये 359/– प्रतिदिन + EPF@13% + ESI@3.25% आदि जो 10851/– रूपये प्रतिमाह प्रति मशीन से कम नहीं होगी। (EPF एवं ESI की दरें नवीनतम आदेशों के अधीन रहेगी।)

Prakash

एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

10. वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेश इस निविदा में लागू होंगे। संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई. एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
11. संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटे श्रमिकों के ई.पी.एफ. और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्बन्धित चालान की प्रति प्रस्तुत किए जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भुगतान किया जायेगा।
12. सेवा एजेन्सी द्वारा अवयस्क व्यक्तियों को कार्य पर नहीं लगाया जायेगा तथा नियोजित कम्प्यूटर ऑपरेटर को श्रम अधिनियम के अन्तर्गत स्किल्ड लेबर (Skilled) की निर्धारित न्यूनतम वेजेज (पारिश्रमिक/वेतन) राशि दिया जाना अनिवार्य होगा, उसी अनुरूप दरें प्रस्तुत करनी होगी। कोई भी निविदा न्यूनतम मजदूरी से कम दर की स्वीकार नहीं की जावेगी।
13. निविदादाता द्वारा ऑपरेटर्स को भुगतान The payment of wages Act, 1936 के Section 5(4) के अनुसार आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से करना अनिवार्य होगा।
14. श्रम विधि के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत रखे जाने वाले समस्त रिकार्ड को सुरक्षित करने की सेवा एजेन्सी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी।
15. निविदा में भाग लेने वाली एजेन्सी पिछले पाँच वर्षो के दौरान राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ब्लैकलिस्टेड नहीं होनी चाहिए।
16. संविदा पर लगे श्रमिकों की किसी भी कारण मृत्यु हो जाती है या अन्य किसी भी रूप में दुर्घटना/घायल/अपंग हो जाता है तो उसकी समस्त जिम्मेदारी एवं क्षतिपूर्ति/मुआवजा आदि देने का भार सेवा एजेन्सी द्वारा वहन किया जावेगा। इसके लिए इस कार्यालय द्वारा कोई भार वहन नहीं किया जायेगा।
17. निविदा स्वीकृत होने पर 7 दिवस के अन्दर–अन्दर निविदादाता को 15000/– रूपये के स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
18. किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति/दण्ड की राशि सेवा एजेन्सी का देय किसी भी प्रकार के भुगतान अथवा अमानत राशि में से वसूल करने का अधिकार नगर निगम जयपुर हैरिटेज का होगा।
19. सेवा आपूर्ति संस्था के स्तर पर उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों का चाल–चलन अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में सेवा एजेन्सी की पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
20. निविदादाता वाणिज्य कर विभाग राजस्थान में रजिस्टर्ड एवं GST नम्बर धारक होना चाहिए। निविदादाता के पास PAN कार्ड होना चाहिए। निविदा दाता के पास श्रम विभाग द्वारा जारी श्रम प्रदायक लाइसेन्स होना चाहिए। निविदा दाता PF लाईसेन्स

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

धारक होना चाहिए। साथ ही निविदादाता फर्म द्वारा वर्तमान में या पूर्ववर्ती बारह मासों के किसी भी दिन 50 या इससे अधिक कर्मचारी नियोजित किये गये हो तो ऐसे निविदादाता को राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970 से पंजीकृत प्रमाण–पत्र संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा।

21. अनुबन्ध प्रारम्भ में एक वर्ष की अवधि के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य रहने पर दोनों पक्षों की सहमती से अधिकतम एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। इस निमित्त वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश इस संविदा पर लागू रहेंगे।
22. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निम्न वर्णित स्तर के होने चाहिए (Minimum Requirement) :–

Computer- Processer Intel Core i3 / Equivalent AMD based Computer or higher speed, RAM 4 GB or higher, Hard disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger, 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD Writer, Standard Keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

Printer- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more. For specific needs, Dot Matrix I inkjet printer may be taken in lieu of laser printer.

UPS:- Online/Offline UPS for above Computer and Printer with 30 minutes battery backup.

Manpower : The personnal should be graduate and should have knowledge to operate computer in windows environment, good knowledge/Practice of MS- office word Processer, Internet operations and should have sufficient speed of typing in Hindi 30 w.p.m. & English 25 w.p.m.

23. अनुबन्ध से पूर्व सफल निविदादाता को उपयुक्त ऑपरेटर्स की सूची मय योग्यता प्रस्तुत करनी होगी। जिन व्यक्तियों की सेवायें अनुबन्धकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। ऑपरेटर्स की योग्यता निविदा प्रपत्र के अनुसार रहेगी।
24. सफल निविदादाता के माध्यम से ऑपरेटर्स मय मशीन के सेवायें ली जायेगी जिनकी संख्या आवश्यकतानुसार घटाई/बढ़ाई जा सकेगी।
25. कम्प्यूटर यूनिट की स्थापना के बाद उनका निरीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेसीफिकेशन के अनुरूप है। यदि सिस्टम विहित स्पेसीफिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया गया तो सम्बन्धित फर्म को दो दिवस में निर्धारित स्पेसिफिकेशन अनुसार कम्प्यूटर यूनिट स्थापित करनी होगी। ऐसा ना करने पर 500/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से शास्ती लगाई जायेगी।
26. कम्प्यूटर यूनिट स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली की फिटिंग की व्यवस्था नगर निगम स्तर पर की जावेगी। नगर निगम द्वारा यह सुविधा भी प्रदान की जावेगी कि कार्यालय बन्द होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सकें।
27. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। माह में राजकीय अवकाश के अतिरिक्त कोई अवकाश नहीं होगा, आवश्यकता पड़ने पर राजकीय अवकाश को भी बुलाया जायेगा। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जावेगा, तत्पश्चात् विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हेरिटेज
जयपुर

28. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अधिक कम्प्यूटर बंद नहीं रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर ही किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 500/– रूपये की कटौती की जावेगी।
29. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करने होंगे एवं यदि बढी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे पर करवा कर देना होगा।
30. कम्प्यूटर सिस्टम का सही तरीके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी। इसके लिए किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्मत करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में एक दिन से अधिक समय लगने की सम्भावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण (Stand By) लगाने की व्यवस्था करनी होगी।
31. यदि कम्प्यूटर सिस्टम सम्बन्धित विभाग की सन्तुष्टि के अनुसार कार्य नहीं करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर फर्म का अनुबन्ध निरस्त (Repudiate) किया जा सकेगा एवं पैनल से हटा दिया जायेगा।
32. यदि उपकरणों की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी सम्बन्धित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणों का बीमा करवा सकता है।
33. प्रत्येक माह की समाप्ति पर निविदाकार द्वारा सम्बन्धित शाखा प्रभारी द्वारा सन्तोषप्रद रूप से कार्य सम्पन्न किये जाने का प्रमाणीकरण पत्र प्रोग्रामर के सम्मुख प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् उन प्रमाणपत्रों के आधार पर प्रोग्रामर द्वारा प्रमाणपत्रों के साथ बिल प्रस्तुत करने पर बिल भुगतान चैक/आर.टी.जी.एस. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।
34. समस्त विधि कार्यवाही यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी भी प्रकार पक्षकार (जयपुर नगर निगम हैरिटेज व ठेकेदार) द्वारा जयपुर में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।
35. कम्प्यूटर सेवाओं के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नहीं किया जावेगा।
36. फर्म का कार्यालय, जयपुर शहर में स्थित होना चाहिए।
37. पैनल में शामिल समस्त फर्मो का कार्य आंवटन उनकी तकनीकी एवं वित्तीय क्षमता कार्यशैली एवं कार्य की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा। फर्मो का कार्य आंवटन हेतु नगर निगम पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहेगा एवं इस संबंध में कोई विवाद मान्य नहीं होगा और न ही इस संबंध में नगर निगम निविदाकार को कोई स्पष्टीकरण देने हेतु बाध्य होगा।
38. विभिन्न फर्मो से बनाये जा रहे पैनल में फर्मो की अधिकतम संख्या नगर निगम जयपुर द्वारा अपने कार्य की आवश्यकता के अनुरूप निर्धारित की जावेगी।
39. फर्म को आंवटित कम्प्यूटर मय ऑपरेटर की संख्या आवश्यकतानुसार घटाई अथवा बढाई जा सकती है।

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

40. कार्य सन्तोषप्रद नहीं होने अथवा कार्य नहीं करने की स्थिति में अमानता राशि जब्त की जा सकती है और कार्य सन्तोषप्रद होने की स्थिति में ही रिफण्डेबल होगी, जो कि पैनल में शामिल फर्म को कार्यावधि समाप्ति के पश्चात्, कोई कटौती या अन्य वसूली जो भी कोई हो, करने के पश्चात् लौटा दी जावेगी।
41. चयनित फर्मो को जारी कार्यादेश दिनांक से अधिकतम 7 दिवस की अवधि में निर्धारित स्पेसिफिकेशन की कम्प्यूटर मय ऑपरेटर नगर निगम जयपुर के कार्यालय में आदेशानुसार स्थापित करने होगें।
42. कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम प्रदाय आदेश की रकम की पाँच प्रतिशत या जैसा कि निविदा दस्तावेज में विनिर्दिष्ट की जाए होगी। कार्य सम्पादन प्रतिभूति नगर निगम जयपुर की वैबसाईट www.jaipurmcheritage.org पर जाकर जमा करवानी होगी एवं उक्त का समायोजन सफल निविदा दाता की निविदा राशि में किया जावेगा।
43. निविदादाता द्वारा एक कम्प्यूटर पर केवल और केवल एक ही ऑपरेटर नियोजित किया जाना मान्य होगा। यदि ऐसा प्राप्त नहीं हुआ तो निविदादाता को पैनल से निरस्त करने का अधिकार नगर निगम जयपुर का रहेगा।
44. केन्द्र सरकार व राज्य सरकार के समय–समय पर जारी नियमों व परिपत्रों की पालना करनी होगी।
45. निविदाकर्ता फर्म का किसी भी राजकीय विभागो/निगम/बोर्ड में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने के कार्य में गत तीन (3) वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (केवल कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध करने से संबंधित कार्य के लिए) 15 लाख अथवा सकल तीन (3) वर्ष का कुल 45 लाख जिसमें किसी एक वर्ष का 15 लाख हो एवं 15 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर न्यूनतम एक वर्ष तक निरन्तर उपलब्ध कराने का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
46. संस्था पूर्व में डिफॉल्टर एवं दिवालिया नहीं हो।
47. बोलीदाता/संवेदक/सेवा प्रदाता को राज्य सरकार/निगम/बोर्ड में न्यूनतम 15 कम्प्यूटर यूनिट मय ऑपरेटर उपलब्ध करवाने के अनुभव प्रमाण पत्र, आदेशों, अनुबंध की प्रतियां बोली के तकनीकि प्रस्ताव के साथ संलग्न/अपलोड करनी आवश्यक है।
48. जयपुर नगर निगम एवं कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के बीच कोई भी स्वामी सेवक का संबंध नहीं होगा। इनका संबंध सेवा प्रदाता संस्था तक ही सीमित रहेगा। इनका विभाग से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी प्रकार का संबंध नहीं होगा।
49. विभाग द्वारा नियमानुसार आयकर टी.डी.एस. की कटौती करते हुए भुगतान किया जायेगा।
50. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी, जो स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी।

नोट :– ई–टेण्डरिंग सिस्टम के प्रशिक्षण हेतु DOIT & C विभाग द्वारा नियमित रूप से प्रशिक्षण आयोजित किए जाते है अतः इच्छुक निविदादाता प्रशिक्षण हेतु निम्न पते पर सम्पर्क कर सकता है।

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

E-Procurement Cell, RISL, योजना भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर।
टेलिफोन नम्बर :– 0141–4022688, 180030702232 (हैल्प डैस्क)

मैंने उक्त शर्तो (1 से 49) का अच्छी तरह अध्ययन कर लिया है। मुझे/हमें यह भी स्वीकार्य है कि नगर निगम जयपुर हैरिटेज का निर्णय हमारे लिये सर्वोपरी होगा।

निविदा दाता के हस्ताक्षर :– ....

नाम व पता :– ....

....

....

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पास, बडी चौपड, जयपुर, राजस्थान–302002)

क्रमांकः एफ4( )/अति.आ./न.नि.ज.है/कम्प्यू/2024/561 दिनांक 15/02/2024

फोन नं. :– 9887764012, E-mail :– progheritage@gmail.com

तकनीकी ई–निविदा सूचना संख्या 5/2023–24 प्रपत्र

1. वर्ष 20214–25 में पूर्णतः अस्थायी तौर पर अनुबन्ध पर कम्प्यूटर मय ऑपरेटर के पैनल में सम्मिलित करने हेतु निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/सेवा एजेन्सी का नाम :–...
3. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म/सेवा एजेन्सी का पता :–.. फोन नं. .... मोबाईल नं. ....
4. संदर्भित व्यक्ति का नाम :–.. फोन/मोबाईल नं. ....
5. हम कार्यालय हाजा द्वारा जारी निविदा सूचना सं. .... दिनांक .... में वर्णित सभी शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गई उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते है। इनके सभी पृष्ठों पर उनमें उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण में हमने हस्ताक्षर किये है।
6. सेवा प्रदाता ऐजेन्सी से सम्बन्धित तकनीकी योग्यता सम्बन्धी विवरण :–
(कृपया प्रत्येक हेतु आवश्यक प्रपत्र/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः संलग्न करें।)

क्र. सं.	विवरण	रजिस्ट्रेशन संख्या	वर्ष	पंजीकरण दिनांक	संलग्नक क्रमांक
1.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम, 1970				
2.	कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952				
3.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948				
4.	वस्तु एवं सेवा कर (GST)				
5.	आयकर (Pan No.)				
6.	राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम 1958 अथवा इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत अथवा इण्डियन एक्ट 1956 के अंतर्गत				

1. बिडिंग डाक्यूमेन्ट फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं बिड सिक्योरिटी राशि की प्राप्ति।
2. निविदाकर्ता फर्म का किसी भी राजकीय विभागो/निगम/बोर्ड में कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने के कार्य में गत तीन (3) वर्ष का वार्षिक टर्नओवर (केवल कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध करने से संबंधित कार्य के लिए) 15 लाख अथवा सकल तीन (3) वर्ष का कुल 45 लाख जिसमें किसी एक वर्ष का 15 लाख हो एवं 15 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर उपलब्ध कराने के कार्य आदेश आवश्यक एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है।
3. हस्ताक्षरित बिड डाक्यूमेन्ट एवं सैल्फ डिक्लियरेशन।(संलग्न सूची "ब")
4. सैल्फ डिक्लियरेशन की आपकी फर्म राज्य सरकार के किसी भी विभाग द्वारा बलैकलिस्टेड नहीं है, दिवालीया नहीं है एवं डिफाल्टर नहीं है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पास, बडी चौपड, जयपुर, राजस्थान–302002)

क्रमांकः एफ4( )/अति.आ./न.नि.ज.है/कम्प्यू/2024/561 दिनांक 15/02/2024

अनुसूची "ब" योग्यता के सम्बन्ध में निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम, 2012 की धारा 7 के अन्तर्गत मेरी/हमारी निविदा के सम्बन्ध में जो कि प्रस्तुत है .... में उपापन हेतु आपके निविदा आमंत्रित सूचना क्रमांक .... दिनांक .... के क्रम में घोषणा करता हूँ / करते हैं कि :–

1. आवश्यक वृत्तिक, तकनीकी, वित्तीय और प्रबन्धकीय स्त्रोत तथा उपापन संस्था द्वारा किये गये निविदा दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या यथास्थिति, निविदा लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों द्वारा अपेक्षित सक्षमता धारित करेगा,
2. ऐसे करों को संदत्त करने की, जो निविदा दस्तावेजों, पूर्व–अर्हता दस्तावेजों या निविदा लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विनिर्दिस्ट किये गये अनेसार केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या, यथास्थिति, किसी स्थानीय प्राधिकारी को संदेय हैं, अपनी बाध्यता की पूर्ति करेगा,
3. दिवालिया, रिसीवर के अधीन, शोधन अक्षम नहीं होगा या परिसमापन नहीं कर रहा होगा, न किसी न्यायालय या किसी न्याधिक अधिकारी द्वारा प्रशासित कार्यकलाप रखेगा, न अपने कारबार के क्रियाकलाप निलंबित रखेगा और न पूर्वगामी कारणों में से किसी के लिए भी विधिक कार्यवाहियों के अध्यधीन होगा,
4. अपने वृत्तिक आचरण चा उपापन प्रक्रिया के प्रारम्भ के पूर्ववर्ती तीन वर्ष की किसी कालावधि के भीतर काई उपापन संविदा किये जाने के लिए अपनी अर्हताओं के बारे में मिथ्या कथन करने या दुर्व्यपदेशन सम्बन्धी किसी दांडिक अपराध के सम्बन्ध में न तो स्वयं, और न उनके निदेशक और अधिकरी दोषसिद्ध हुए हैं, या विवर्जन कार्यवाहियों के अनुसरण में अन्यथा निरर्हित हुए हैं,
5. ऐसे हित, जो पूर्व–अर्हता के दस्तावेजों, निविदा लगाने वाले के रजिस्ट्रीकरण दस्तावेजों में विहित और विनिर्दिष्ट किये जायें, के प्रति कोई विरोध नहीं रखेगा, जो उचित प्रतियोगिता को तात्विक रूप से प्रभावित करे,
6. कोई भी अन्य अर्हताएँ, जो विहित की जायें, पूर्ण करेगा।

दिनांक :– ....

स्थान :– ....

निविदादाता के हस्ताक्षर ....

निविदादाता का नाम :– ....

पद :– ....

पता :– ....

....

Prakash

एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

(a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) disclose conflict of interest, if any; and

(h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

a. have controlling partners/ shareholders in common; or
b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to .... for procurement of .... in response to their Notice Inviting Bids No.............. Dated............. I/we hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012, that:

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date:
Place:

Signature of bidder
Name :
Designation:
Address:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is COMMISSIONER NMJH

The designation and address of the Second Appellate Authority is ________________

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

(a) determination of need of procurement;
(b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
(c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
(d) cancellation of a procurement process;
(e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

(a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

(a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.

(b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-

- (i) hear all the parties to appeal present before him; and
- (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1

[See rule 83]

Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012

Appeal No ....of ....

Before the .... (First / Second Appellate Authority)

1. Particulars of appellant:
   (i) Name of the appellant:

   (ii) Official address, if any:

   (iii) Residential address:

2. Name and address of the respondent(s):
   (i)
   (ii)
   (iii)
3. Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved:
4. If the Appellant proposes to be represented by a representative, the name and postal address of the representative:
5. Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:
6. Grounds of appeal: .... (Supported by an affidavit)
7. Prayer: ....

Place ....

Date ....

Appellant's Signature

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and

iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

3. **Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)**

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.

Annexure E

Clause 1: Fair Wage Clause

(a) The Contractor shall pay not less than fair wages/minimum wages to labours engaged by him on the work as revised from lime to time by the Government, but the Government shall not be liable lo pay any thing extra for it except as stipulated in price escalation clause (clause 45) of the agreement.

Explanation: "Fair Wage" means minimum wages for time or piece work, fixed revised, by the Stale Government under the Minimum Wages Act, 1948.

(b) The Contractor shall, notwithstanding the provision of any contract to the contrary, cause to be paid fair wages lo labourers indirectly engaged on the work, including any labour engaged by his sub-con tractors in connection with the said work as if the labourers have been immediately or directly employed by him.

(c) In respect of all labourers, immediately or directly employed on the work, for the purpose of the Contractor's part of this agreement, the Contractor shall comply with or cause to be complied with the Public Works Department Contractor's Labour Regulations made, or that may be made by the Government, from time to time, in regard lo payment of wages, wage period, deductions from wages, recovery of wages not paid, and unauthorised deductions, maintenance of wages register, wage card, publication of scale of wages and other terms of employment, inspection and submission of periodical returns and other matters of a like nature.

(d) The Engineer-in-charge shall have the right to deduct from the money due to the Contractor any sum required or estimated lo be required for making good the loss suffered by a worker or workers, by reasons of non-fulfilment of the conditions of the contract, for the benefit of the worker or workers, non-payment of wages or of deductions made there from, which are not justified by the terms of the contract, or as a result of non-observance of the aforesaid regulations.

(e) Vis-à-Vis the Municipal Corporation Jaipur, the Contractor shall be primarily liable for all payments to be made and for the observance of the regulations aforesaid, without prejudice lo his right to claim indemnity from his subcontractors,

(f) The regulations, aforesaid, shall be deemed to be part of this contract and any breach, thereof, shall be breach of the contract.

Clause 2: Contractor to engage technical staff

The Contractor shall engage the technical staff, as follows, on the contract works:-

(a) For works costing Rs. 100 lac and above- One Graduate Engineer.

(b) For works costing between Rs. 50 lac to Rs. 100 lac- One qualified diploma holder having experience of not less than 3 years.

(c) For works costing between Rs. 15 lac and Rs. 50 lac- One qualified diploma holder.

The technical staff should be available at site, whenever required by Engineer-in-charge to take instructions.

Clause 3 :
The Contractor shall comply with the provisions of the Apprenticeship Act, 1961, and the Rules and Orders issued, there under, from time to time. If he fails to do so, his failure will be a breach of contract. The Contractor shall also be liable for any pecuniary liability arising on account of any violation by him of the provisions of the said Act.

Clause 4: <u>Safety Code</u>
The Contractor shall follow the safety code of electricity Strictly.

Clause 5:
<u>Near Relatives barred from tendering</u>
The Contractor shall not be permitted to lender for works in Circle, in which his near relative is posted as Divisional Accountant or as an officer in any capacity between the grades of the Superintending Engineer and Assistant Engineer (both inclusive). He shall also intimate the names of persons, who are working with him in any capacity, or are subsequently employed by him and who are near relatives to any gazetted officer in the Organization/Department. Any breach of this condition by the Contractor would render him liable to be removed from the approved list of contractors of the Department. If such facts is noticed (a) before sanction of tender, his offer shall be declared in valid and earnest money shall be forfeited, (b) after sanction of the tender then the tender sanctioning authority may at his discretion forfeit his earnest money, performance guarantee, security deposit and enlistment deposit and the work/remaining work may allot to any registered contractor on the same rates as per rules.

Note: By the term 'near relative' is meant wife, husband, parents and grand-parents, children and grand children, brothers and sisters, uncles and cousins and their corresponding in-laws.

Clause 6<u>: Retired Gazetted Officers barred for 2 years</u>
No Engineer of Gazetted rank or other Gazetted Officer, employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering Department of the Government of Rajasthan, is allowed to work as a Contractor for a period of 2 years of his retirement from Government service without the previous permission of Government of Rajasthan. The contract is liable to be cancelled, if either the Contractor or any of his employees is found, at any time, to be such a person, who had not obtained the permission of Government, as aforesaid, before, submission of the tender or engagement in the contractor's service, as the case may be.

Clause 7<u>: Quality Control</u>
The Municipal Corporation Jaipur shall have right to exercise proper Quality Control measures. The Contractor shall provide all assistance to conduct such tests and shall bear the cost of all tests.

Clause 8:
The work (whether full constructed or not) and all materials, machines, tools and plant, scaffolding,

temporary buildings and other things connected therewith, shall be at the risk of the contractor until the work has been delivered to the Engineer- in -charge, and a certificate from him, to the effect, obtained.

Clause 9: Death of Contractor

Without prejudice to any of the rights or remedies under the contract, if the Contractor dies the legal heirs of the Contractor or the Chief Engineer or duly authorised Engineer shall have the option of terminating the contract without any compensation.

Clause 10 : Force Majeure

Neither party shall be liable to each other, for any loss or damage, occasioned by or arising out of acts or God such as-unprecedented floods, volcanic eruptions, earthquake of other invasion of nature and other acts.

Clause 11: General Discrepancies and errors:

In case of percentage rate tenders, if there is any typographical or clerical error in the rates shown by the department in the "G" Schedule. the rates as given in the basic Schedule of Rates of the Department for the area shall be taken as correct.

Clause 12 : Post payment Audit & Technical Examination:

The Government shall have right to provide a system of per-check of Contractor's bill by a specified Organization, and payment by an Engineer or an Accounts Officer/ Sr. Accounts Officer/ Chief Accounts Officer/ Financial Advisor, as the Government may in its absolute discretion prescribe. Any over-payments/ excess payment detected, as a result of such per-check post-check of Contractor's bill, can be recovered from the contractor's bills in the manner, herein before provided and the Contractor will refund such over/ excess payments.

Clause 13 : Check Measurements:

The department reserves to itself, the right to prescribe a scale of check measurement of work in general, or specific scale for specific works of by other special orders (about which the decision on the department shall be final) Checking of measurement by superior officer shall supersede measurements by the subordinate officer and the former will become the basis of the payment. Any over/excess payment detected, as a result of such check measurement or otherwise at any stage up to the date of completion and the defect removal period specified else-where in this contract, shall be recoverable from the Contractor, as any other dues payable to the Government.

Clause 14: Check Measurements:

The Contractor in course of the work should understand that all materials e.g. stone, bricks, steel and other materials obtainable in the work by dismantling etc. will be considered as the property of the Government and will be disposed off to the best advantage on the Government. As per direction of the Engineer-in-Charge.

Clause 15: Recovery from Contractors:

Whenever any claim against the Contractor for the payment of a sum of money arises out of or under the contract, the Department shall be entitled to recover such sum be appropriation in part or whole of the Performance Guarantee and / or Security Deposit. Security Deposit at the time of enlistment of the Contractor. In the event of the security being insufficient, or if no security has been taken, thereafter, may become due to the Contractor, under this or any other contract with the Governor of Rajasthan. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the Contractor shall pay to the Department on demand the balance remaining dues.

The department shall, further, have the right to affect such recoveries under Public Demands Recovery Act.

Clause 16: Jurisdiction of Court:

In the event of any dispute arising between the parties hereto, in respect or any of the matters comprised in this agreement, the same shall be settled by a competent court having jurisdiction over the place, where agreement is executed any by no other court, after completion of proceedings under Clause 23 of this contract.

Annexure F: Form of Bid-Securing Declaration

Date:
Bid No. :
Alternative No. :

To, :
....
....

We, the undersigned, declare that:
We understand that, according to your conditions, bids must be supported by a Bid-securing Declaration. We accept that we are required to pay the bid security amount specified in the Term and Condition of Bid, in the following cases, namely:-

(a) when we withdraw of modify our bid after opening of bids;
(b) when we do not execute the agreement, if any, after placement of supply/work order within the specified period;
(c) when we fail to commence the supply of the goods or service or execute work as per supply/work order within the time specified;
(d) when we do not deposit the performance security within specified period after the supply/work order is placed; and
(e) if we breach any provision of code of integrity prescribed for bidding specified in the Act and Chapter VI of these rules.

In addition to above, the State Government shall debar us from participating in any procurement process undertaken for period not exceeding three years in case where the entire bid security or any part thereof is required to be forfeited by procuring entity.
We understand this Bid Securing Declaration shall expire if:-

(i) we are not the successful Bidder;
(ii) the execution of agreement for procurement and performance security is furnished by us in case we are successful bidder;
(iii) Thirty days after the expiration of our Bid.
(iv) the cancellation of the procurement process; or
(v) the withdrawal of bid prior to the deadline for presenting bids, unless the bidding documents stipulate that no such withdrawal is permitted.

Signed:--------------------------------------
Name:--------------------------------------
In the capacity of:------------------------
Duly authorized to sing the bid for and on behalf of:
Dated on day of
Corporate Seal--

[Note: In case of a Joint Venture, the Bid Securing Declaration must be signed in name of all partners of the Joint Venture that is submitting the bid].

कार्यालय नगर निगम जयपुर हैरिटेज

(हवामहल के पास, बडी चौपड, जयपुर, राजस्थान–302002)

क्रमांकः एफ4( )/अति.आ./न.नि.ज.है/कम्प्यू/2024/ दिनांक

वित्तीय – निविदा

Name of Work :- कम्प्यूटर मय ऑपरेटर पैनल सप्लाई दर अनुबंध वर्ष 2023–24

क्र. सं.	कार्य की प्रकृति	श्रम विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी प्रतिमाह	सेवा प्रदाता द्वारा प्रस्तुत दर प्रति व्यक्ति प्रतिमाह जो न्यूनतम दर से कम न हो	ईपीएफ दर 13%	ईएसआई दर 3.25%	कम्प्यूटर उपकरण किराया	सेवा प्रदाता का सर्विस चार्ज राशि	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	कम्प्यूटर मय ऑपरेटर आपूर्ति	9334						

बोलीदाता द्वारा कॉलम संख्या 4,7 एवं 8 की अनिवार्यतः पूर्ति कर अपनी दरें BOQ में प्रस्तुत करें।

1. जी.एस.टी. का नियमानुसार पृथक से देय होगा। वित्तीय बोली में उल्लेख नहीं करें।
2. बोली के साथ संलग्न शर्तो एवं कार्य विवरण के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय
मोहर एवं मो.नं.

Prakash
एसीपी (उपनिदेशक)
नगर निगम हैरिटेज
जयपुर